एसआर. संभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक, इंडियन ऑयल

निगम लि. पोआ होल्डर और ओआरएस के माध्यम से।

बनाम

अशोक शंकरलाल ग्वालानी (सिविल अपील क्रमांक 9101 ऑफ़ 2012)

दिसंबर 14, 2012

[स्वतंत्र कुमार और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.जे.]

सार्वजनिक वितरण -पेट्रोल/डीजल डीलरशिप का आवंटन -आवंटन के लिए चयन का पहला दौर चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया दूसरे दौर में - चयन में, प्रतिवादी का चयन किया गया - यह चयन भी अनियमितताओं के कारण रद्द कर दिया गया - चयन के तीसरे दौर में, प्रतिवादी की उम्मीदवारी खारिज प्रतिवादी द्वारा अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कंपनी को प्रतिवादी के पक्ष में आशय पत्र जारी करने का निर्देश दिया - अपील पर, माना गया: चयन रद्द करने का निर्णय सक्षम द्वारा लिया गया था प्राधिकार -उच्च न्यायालय को भारत के संविधान, 1950 -अनुच्छेद 226 के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

अपीलकर्ता-कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों के लिए पेट्रोल/डीजल खुदरा दुकानों (डीलरशिप) के अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रतिवादी ने अन्य लोगों के साथ एक स्थान के लिए आवेदन किया। चयन प्रक्रिया के पहले दौर में, 'के' का चयन साक्षात्कार और स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया गया था। उत्तरदाता को साक्षात्कार समिति और स्क्रीनिंग समिति द्वारा योग्यता सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया था। शिकायत पर जांच अधिकारी ने प्रतिवादी को प्रथम स्थान पर रखा। अंततः चयन रद्द कर दिया गया और सभी अभ्यर्थियों को पुनः साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इस प्रकार चयन के दूसरे दौर में पुनः साक्षात्कार के बाद, योग्यता पैनल में केवल प्रतिवादी उम्मीदवार पाया गया। इसके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज कराई गईं। शिकायतों की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किया गया। कंपनी के खिलाफ 'के' द्वारा आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका भी दायर की गई थी, जिसके तहत मेरिट सूची जहां उन्हें नंबर 1 उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जांच के बाद, शिकायतों में दम पाया गया और इसलिए, कंपनी ने फिर से सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का विज्ञापन दिया। इस प्रकार तीसरे दौर में चयन, समिति, जिसके समक्ष सभी योग्य उम्मीदवारों के आवेदन को रखा गया, इस आधार पर खारिज कर दिया गया की प्रतिवादी कि उम्मीदवारी

रिलेशनशिप एफिडेविट' फॉर्मेट के मुताबिक नहीं था। प्रतिवादी की रिट याचिका, जिसकी अस्वीकृति को चुनौती दी गई है उनकी उम्मीदवारी को उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी थी। इसलिए वर्तमान अपील.

न्यायलय ने अपील स्वीकार किया

आयोजित: 1. साक्षात्कार समिति, स्क्रीनिंग समिति और जांच अधिकारी ने तीन अलग-अलग समूहों में तीन उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जिसके कारण साक्षात्कार समिति, स्क्रीनिंग समिति और जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में उम्मीदवारों की स्थिति बदल गई। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन पर चर्चा की और 24.12.2008 (अर्थात जिस दिन प्रतिवादी को चयन के दूसरे दौर में योग्यता सूची में रखा गया था) के बाद आगे के घटनाक्रमों पर चर्चा किए बिना अपीलकर्ताओं को पत्र जारी करने का निर्देश दिया। हालाँकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस रुख पर गौर किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 'रिलेशनशिप शपथ पत्र' प्रारूप के अनुसार नहीं था, लेकिन यह चयन के मामले में इस तरह के अधूरे हलफनामे के प्रभाव पर चर्चा करने में विफल रहा। [पैरा 15 और 16] [1139-एफ-एच; 1140-ए]

एफ एसआर. प्रभाग. आरईटी. सेल्स एमजीआर., 1.0.सी.एल. टी.आर. पीओए होल्डर बनाम अशोक 1127

2. आम तौर पर, यदि किसी पैनल के चयन या तैयारी के मामले में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो खराब पाए जाने वाले पैनल को फिर से व्यवस्थित करने के बजाय नए सिरे से चयन करना वांछनीय है। वर्तमान मामले में,प्राधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है,यह निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि क्या पैनल को हटा दिया जाना चाहिए और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से चयन किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को चयन रद्द करने में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी को संबंधित पेट्रोल/डीजल खुदरा दुकानों को फिर से विज्ञापित करने और कानून के अनुसार नया चयन करने की स्वतंत्रता के साथ विवादित आदेश को रद्द कियाजाताहै।[पैरा17 और 18][1140-बी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या डी 9101/2012

2010 के डब्लूपी संख्या 5032 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.09.2010 से।

जी.ई. वाहनवती, एजी, जयदीप गुप्ता, राहुल नारायण,मीनाक्षी अरोड़ा, प्रशांत भूषण, सुमीत शर्मा, संजीव

कुमार सक्सेना,रूचि मिश्रा, प्रथा सिल और कुमार चैटर्जी उपस्थित पक्षों के लिए. न्यायालय का निर्णय सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे. 1 द्वारा सुनाया गया।

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. वर्तमान अपील बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 2010 की रिट याचिका संख्या 5032 में पारित दिनांक 29 सितंबर, 2010 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने इंडियन ऑयल कंपनी को श्री अशोक शंकरलाल ग्वालानी (इसके बाद "प्रतिवादी" के रूप में संदर्भित) ठाणे बेलापुर रोड, ग्राम महापे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित साइट के लिए डीलरशिप आवंटित करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट को मंजूरी दे दी है।

3. अपीलकर्ता द्वारा बताए गए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं

11 जून, 2005 को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बाद में "कंपनी" के रूप में संदर्भित) ने प्रमुख समाचार पत्रों में एक उद्घोषणा प्रकाशित की और महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न स्थानों के लिए पेट्रोल/डीजल खुदरा दुकानों (डीलरशिप) के अनुदान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। 14 जुलाई, 2005 को प्रतिवादी ने अन्य लोगों के साथ इसके लिए आवेदन किया। साक्षात्कार 9-10 दिसंबर, 2005 को आयोजित किए गए थे। श्री नीलेश एल. कुडालकर को योग्यता पैनल में शीर्ष पर रखा गया था, जबकि प्रतिवादी को दूसरे और श्री के. श्रीनाधा राव को तीसरे स्थान पर रखा गया था। हालाँकि, शीर्ष तीन उम्मीदवारों के अंकों के बीच अंतर 5% के भीतर था, इसलिए कंपनी की 7 अप्रैल, 2005 की नीति के अनुसार साक्षात्कार के

परिणाम को स्थगित रखा गया था। एक स्क्रीनिंग कमेटी की स्थापना की गई जिसने तीन उम्मीदवारों के एक और साक्षात्कार की समीक्षा की और कार्यान्वित किया गया। परिणाम 4 अप्रैल, 2006 को घोषित किया गया और श्री नीलेश एल. कुडालकर मेरिट पैनल में प्रथम स्थान पर थे।

4. व्यथित होकर प्रतिवादी और श्री के. श्रीनाधा राव दोनों ने चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए क्रमशः 10.4.2006 और 19.4.2006 को कंपनी में शिकायत की। दिनांक 01 सितंबर 2005 की नीति के अनुसार कंपनी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की गई। अन्य बातों के अलावा, यह पाया गया कि प्रतिवादी और श्री श्रीनाधा राव को उनकी वित्तीय क्षमता के संबंध में सही ढंग से चिह्नित नहीं किया गया था और जैसा कि विज्ञापन के तहत विशेष रूप से आवश्यक था दोनों सत्यापित दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहे थे। चूंकि शिकायतों में लगाए गए आरोपों में दम पाया गया, इसलिए चयन रद्द कर दिया गया और सभी उम्मीदवारों को दोबारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इस बीच, 28 अप्रैल, 2006 को, श्री प्रीतेश छाजेड़, जो साइट पर काम करने वाले एक एम एंड एच ठेकेदार थे, ने ठाणे सीनियर डिवीजन कोर्ट के समक्ष सिविल सूट नंबर 230/2006 दायर किया और कंपनी के खिलाफ उसे अनुबंध कर जमीन से बेदखल करने के तहत निषेधाज्ञा को समाप्त करने की मांग की। वह इसमें असफल रहने पर उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने 27 जून, 2008 को

खारिज कर दिया और उन्हें 31 दिसंबर 2008. के लिए साइट खाली को करने कहा गया।

5. 22 और 24 दिसंबर, 2008 को पुनः साक्षात्कार आयोजित किए गए। प्रतिवादी को मेरिट पैनल में एकमात्र बी उम्मीदवार पाया गया। हालाँकि, श्री प्रीतेश छाजेड़ (जो साक्षात्कार में भी शामिल हुए थे) से 26 दिसंबर, 2008 को और श्री के. श्रीनाधा राव से 16.12.2008, 23.12.2008, 30.12.2008, 2.01.2009 और 10.02.2009. को शिकायतें प्राप्त हुईं। पुनः 30.12.2008 को शिकायतों में निहित आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया गया। इसके अलावा 14.1.2009 को, श्री नीलेश एल. कुडालकर ने एक रिट याचिका दायर की। मेरिट सूची को रद्द करने और उसे नंबर 1 उम्मीदवार घोषित करने के लिए कंपनी के खिलाफ 2009 का 113। बंबई उच्च न्यायालय ने अप्रैल, 2009 में उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया।

6. इस बीच, कंपनी द्वारा शुरू की गई जांच से पता चला कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों में दम था।

7. इसलिए, 6 अगस्त, 2009 को अपीलकर्ताओं ने स्थान के पुनः विज्ञापन के लिए अपने प्रबंधन से अनुमोदन मांगा। 18 अगस्त, 2009 को कंपनी प्रबंधन ने चयन प्रक्रिया में सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए प्रारंभिक चरण से सभी दस्तावेजों की जांच सहित सभी उम्मीदवारों के पुनः

साक्षात्कार के लिए विज्ञापन दिया। चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू थी, इसलिए दोबारा साक्षात्कार को इसके हटने तक टाल दिया गया था।

8. दिसंबर, 2009 में एल-1 समिति की नियुक्ति की गई जिसके समक्ष सभी दस पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र अन्य दस्तावेजों सहित रखे गए। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिवादी की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि 'रिलेशनशिप एफिडेविट' प्रारूप के अनुसार नहीं था।

9. 3 जून, 2010 को प्रतिवादी को उनके आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के संबंध में सूचित किया गया।

10. व्यथित प्रतिवादी ने 17.6.2010 को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष WP(C) संख्या 5032/2010 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक उचित रिट जारी करने की प्रार्थना की गई, जिसमें अपीलकर्ताओं को साइट पर डीलरशिप आवंटित करने का निर्देश दिया गया। विज्ञापन दिनांक 11.6.2005 और चयन समिति के दिनांक 24.12.2008 के निर्णय को लागू करने के लिए दिनांक 03.06.2010 के पत्र को रद्द कर दिया गया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

अपीलकर्ताओं के अनुसार, यह देखते हुए कि सभी पूर्व योग्यता पैनल गंभीर त्रुटियों के कारण खराब हो गए थे, जिसमें सभी साक्षात्कारों के संबंध

में प्राप्त शिकायतें भी शामिल थीं, स्थान को फिर से विज्ञापित करके कंपनी नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने की इच्छुक है।

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 8 दिसंबर, 2009 को श्रीनाधराव और श्री प्रीतेश छाजेड़ द्वारा दायर शिकायतों के मद्देनजर एल-आई समिति को नामित किया गया था। इन शिकायतों की गहन जांच की गई और 24 मार्च, 2009 की रिपोर्ट कंपनी को प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने मामले को जांच स्तर से देखने और सभी उम्मीदवारों का दोबारा साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया ताकि चयन प्रक्रिया में खामियों को दूर किया जा सके। सभी आवेदनों की दोबारा जांच की गई और उस प्रक्रिया के आवेदन के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेजों को वापस ले लिया जो पीड़ित पाया गया कमियाँ. दलील दी गई कि जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादी प्रारूप के अनुरूप नहीं था और इसलिए, उसका नीति के अनुसार आवेदन अस्वीकार किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, आक्षेपित पत्र प्रतिवादी को जारी किए गए।

12. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त तथ्य पर विवाद किया गया। उन्होंने कंपनी द्वारा 2009 की रिट याचिका संख्या 113 में दायर हलफनामे को आमंत्रित किया जिसमें उन्होंने चयन प्रक्रिया के साथ-साथ 24.12.2008 को चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची का समर्थन किया। उक्त हलफनामे में,

कंपनी द्वारा इस आरोप का खंडन किया गया कि प्रतिवादी कम मेधावी था। कंपनी का रुख यह था कि प्रतिवादी को डीलरशिप देने का निर्णय किसी भी स्पष्ट त्रुटि, समानता, निष्पक्ष खेल और न्याय से प्रभावित नहीं था। उक्त मामले में, कंपनी ने दलील दी कि प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय पारदर्शी था और ईमानदारी के अलावा किसी अन्य विचार से प्रेरित नहीं था। उक्त मामला दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी के चयन को चुनौती देते हुए दायर किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रिट याचिका संख्या 113/2009 में 17 अप्रैल, 2009 के आदेश के जरिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हाई कोर्ट चयन समिति के फैसले पर अपील नहीं कर सकता और यह फैसला सही नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त मामले (रिट याचिका संख्या 113/2009) के रिट याचिकाकर्ता ने बिना किसी विरोध के बाद के चयन में भाग लिया, वह पिछली चयन प्रक्रिया में वापस नहीं लौट सका।

13. 17 सितंबर, 2012 को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने कंपनी की ओर से पेश हुए विद्वान अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारी हमें चयन प्रक्रिया के पहले और दूसरे दौर को रद्द करने के कारणों को विस्तार से बताएं। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने 22 सितंबर, 2012 को अपने कार्यालय में कंपनी के प्रतिनिधि के साथ बैठक की और साक्षात्कार के प्रासंगिक कागजात देखने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की; जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"चयन प्रक्रिया के पहले दौर के संबंध में, जिसमें साक्षात्कार 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 2005 को आयोजित किए गए थे, स्क्रीनिंग कमेटी ने 4.4.2006 को परिणाम जारी किए थे, जिसके बाद 10.04.2006 को श्री अशोक शंकरलाल ग्वालानी से और 19.4.2006 को श्री के. श्रीनाधा राव से शिकायतें प्राप्त हुईं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महाराष्ट्र राज्य के कार्यालय महाप्रबंधक ने शिकायतों की जांच के संबंध में जांच समिति नियुक्त की। 07 अक्टूबर 2006 को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय ने 17.10.2006 को एक नोट तैयार किया, जिसे अंततः 7 नवंबर 2006 को मंजूरी दे दी गई और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार फिर से निर्णय लिया गया - योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लें क्योंकि योग्यता पैनल में उम्मीदवारों के वित्तीय मापदंडों के मूल्यांकन में त्रुटियों के कारण योग्यता पैनल खराब हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप योग्यता पैनल में बदलाव हुआ। दिनांक 17.10.2006 के नोट की एक टाइप की गई प्रति याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड तथ्यों, बाद की घटनाओं और दस्तावेजों को लाने के लिए आवेदन में संलग्न की गई है, जिसे अनुबंध पी-5 के रूप में चिह्नित किया गया है।

4. चयन प्रक्रिया के दूसरे दौर के संबंध में, जिसमें साक्षात्कार 22-24 दिसंबर, 2008 को आयोजित किए गए थे, श्री प्रीतेश छाजेड़ से 26.12.2008 को और श्री के. श्रीनाधा राव से 16.12.2008 को एक अनुस्मारक के साथ दो शिकायतें प्राप्त हुईं। 10.1.2009 को जांच अधिकारी

द्वारा 24.3.2009 को एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे महाराष्ट्र राज्य कार्यालय द्वारा दिनांक 13.4.2009 के नोट के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया था। श्री प्रीतेश छाजेड़ की शिकायत के संबंध में पाया गया कि शिकायतकर्ता को लाभ दिये जाने पर निम्नलिखित स्थिति सामने आयी।

जांच निष्कर्षों के आधार पर भले ही शिकायतकर्ता उम्मीदवारों श्री प्रीतेश जे. चैजेड को लाभ देने वाला माना जाता है, फिर भी पैनल में शामिल नंबर एक उम्मीदवार मेरिट पैनल में पहले स्थान पर अपरिवर्तित रहता है, हालांकि, अन्य योग्य उम्मीदवार को दूसरी रैंक पर जोड़ने से पैनल बदल जाएगा।

अन्य दो शिकायतकर्ता उम्मीदवार काल्पनिक रूप से नीचे क्रमबद्ध किया गया है"

उम्मीदवार का नाम	L1 समिति द्वारा मार्क	L2 समिति द्वारा मार्क	साक्षात्कार समिति द्वारा आवंटित % अंक (कुल 65 अंकों में से)	साक्षात्कार समिति द्वारा पैनलीकरण	अंको का मूल्यांकन यदि विचलनो को ध्यान में रखा जाये	पैनलबद्धता विचलन पर विचार किये जांए के पश्चात
श्री अशोक ग्वालानी	41.78	5.2	72.38%	1	ना	

श्री प्रीतीश छाजर	35.67	7.4	अपात्र (42.07) (66.26)	अपात्र	66.26%	
श्री के. श्रीनाधा राव	31.00	6.9	58.30	अयोग्य	ना	
श्री केशवराव गोपीराव शिंदे	32.85	5.8	59.46	अयोग्य	ना	

एल1 (अनुलग्नक ए) और एल2 (अनुलग्नक बी) समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर साक्षात्कार समिति (अनुलग्नक सी) द्वारा अनुपालन की गई मार्कशीट, शिकायतकर्ता श्री प्रियतोष छाजेड़ को दिए गए अंकों की गणना उपरोक्त तालिका में की गई है, हालांकि समिति द्वारा उनकी अपात्रता के कारण वही घोषित नहीं किया गया था।)

यह ध्यान में रखते हुए कि श्री प्रीतीश छाजेड़ को एल1 (35.67) और एल2 (7.4) द्वारा आवंटित अंक जोड़े गए हैं, उन्हें 66.26% अंक (यानी 65 में से 43.07) मिलते हैं और वे मेरिट पैनल में दूसरे स्थान पर आ जाते, जिससे मूल मेरिट पैनल दिनांक 23.12.08 में पैनल में शामिल एक उम्मीदवार के बजाय योग्यता पैनल में दो उम्मीदवारों के साथ बदलाव होता है और इस प्रकार चयन ख़राब हो जाता है। इसलिए, प्रचलित नीति

के अनुसार, चूंकि उपरोक्त संदर्भित चयन ख़राब हो जाता है और अन्य पात्र उम्मीदवार भी उपलब्ध हैं, इसलिए सभी पात्र उम्मीदवारों के साथ स्थान का पुनः साक्षात्कार किया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि स्थान महापे को मूल रूप से 11.6.2005 को विज्ञापित किया गया था, जिसके विरुद्ध साक्षात्कार के आधार पर, पहला मेरिट पैनल 4.4.4006 को घोषित किया गया था, उसके बाद शिकायतें थीं और शिकायत निवारण के अनुसार जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रक्रिया और निर्णय के अनुसार, सभी पात्र उम्मीदवारों का पुनः साक्षात्कार 22.12.08 से 24.12.2008 को आयोजित किया गया था और तदनुसार उपरोक्त संदर्भित मेरिट पैनल दिनांक 24.12.2008 को साक्षात्कार समिति द्वारा घोषित किया गया था। इस स्थान के लिए चयन प्रक्रिया पिछले चार वर्षों से अनिर्णीत रही और अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि एक ही स्थान के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों के साथ पुनः साक्षात्कार का मामला होगा। उपरोक्त जांच विवरण और विश्लेषण के आधार पर, पूरी संभावना है ,पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार के संबंध में योग्यता पैनल में कोई और बदलाव नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य उम्मीदवार भी हो सकते हैं जो पैनल में दूसरे और तीसरे स्थान पर आ सकते हैं। हालाँकि प्रचलित नीति के अनुसार पुनः साक्षात्कार की अनुशंसा की गई है।"

5. इसे देखते हुए, मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम फैसले के लिए निम्नलिखित सिफारिशें रखी गईं:-

"1. चूंकि जांच पर उपरोक्त संदर्भित चयन प्रक्रिया विफल हो जाती है और अन्य पात्र उम्मीदवार भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए प्रचलित चयन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पात्र उम्मीदवारों के साथ स्थान का पुन: साक्षात्कार किया जाना चाहिए।

2. हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी, यानी राज्य प्रमुख, एमएसओ उपरोक्त जांच में अंतिम आदेश देते समय (श्री आर. गणेशन द्वारा दिनांक 6.2.2009 और 24.3.2009 की रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि नीचे दिया गया है), यह भी विचार कर सकते हैं उपरोक्त पैरा (सी) में दिए गए तथ्यों पर, क्या मौजूदा मेरिट पैनल दिनांक 24.12.08 को एकमात्र उम्मीदवार के साथ जारी रखा जाए जिसकी स्थिति उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार के रूप में परेशान नहीं हुई है या मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार पुन: साक्षात्कार के लिए जाना है।

3. तालिका में 10 की रिपोर्ट में ऊपर बताए अनुसार मूल मार्कशीट की डुप्लिकेट स्वीकार नहीं करने के लिए डीओ समन्वय अधिकारी और

साक्षात्कार समिति (एल 2) द्वारा की गई चूक को देखते हुए कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।

6. एमएसओ में नई रिटेल टीम द्वारा इन सिफारिशों का अध्ययन/समीक्षा की गई और टिप्पणियां 29.07.2009 को तैयार की गईं, जिन्हें 3.08.2009 को मंजूरी दी गई:

1. चूंकि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी स्थापित हो गई है, जैसा कि सिफारिश की गई है, यह सहमति/अनुशंसा है कि मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार स्थान का फिर से साक्षात्कार किया जाना चाहिए।

2. उपरोक्त क्रम संख्या 1 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी स्थापित की गई है और पुनः साक्षात्कार की अनुशंसा की गई है, चयन में पारदर्शिता लाने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि सभी पात्र उम्मीदवारों के साथ मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार पुनः साक्षात्कार किया जाए।

3. मुख्य प्रबंधक (आरएस), एमएसओ ने डीओ को-ऑर्डिनेटिंग और एल 2 समिति के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है। हमारी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

इस मामले में अभ्यर्थी मूल प्रति की डुप्लीकेट प्रति लेकर आया था, जो पूर्णतः मूल नहीं है। तार्किक रूप से सत्यापन के लिए दस्तावेजों की

डुप्लिकेट प्रति को मूल माना जाना चाहिए था। इसकी समन्वय अधिकारी से पुष्टि करायी जानी चाहिए थी/करानी चाहिए थी।

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि डीओ समन्वयक अधिकारी/एल 2 कमेटी ने इस संबंध में नीति दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया है ताकि साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा लाए जाने वाले मूल दस्तावेज से आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति सत्यापित की जा सके। इसलिए तकनीकी रूप से डीओ समन्वय अधिकारी/एल 2 समिति ने दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया है।

ईडी एमएसओ ने विस्तृत रूप से अपने विचार रखे और अंत में इस प्रकार अपनी राय दी जो है:

"किसी भी आगे की जटिलता से बचने के लिए सभी को उचित मौका दें, मेरी राय में इस चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए) स्थान को पुनः विज्ञापित किया जाना चाहिए। चूंकि इस संबंध में कोई विशिष्ट नीति नहीं है, इसलिए सुझाव दिया गया है कि एचओ की राय मांगी जा सकती है।"

14. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पार्टियों की दलील और रिकॉर्ड से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं: -

उद्घोषणा को 11.6.2005 की गई थी यानी पहले की तुलना में सात साल अधिक लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत डीलरशिप के लिए नहीं गया है।

पहला साक्षात्कार 9-10 दिसंबर, 2005 को आयोजित किया गया था जिसमें श्री नीलेश एल. कुडालकर को योग्यता पैनल में शीर्ष पर रखा गया था, जबकि प्रतिवादी को दूसरे और श्री के. श्रीनाधा राव को तीसरे स्थान पर रखा गया था। जब चयन के खिलाफ शिकायतें की गईं और साथ ही प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया गया, तो जांच के बाद, कंपनी ने पाया कि प्रतिवादी और श्री श्रीनाधा राव को सही ढंग से चिह्नित नहीं किया गया था और जैसा कि विशेष रूप से आवश्यक था दोनों सत्यापित दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहे। और इसलिए विज्ञापन के तहत पहला चयन रद्द कर दिया गया था।

दूसरा साक्षात्कार पुन: बुलाया गया और 22 और 24 दिसंबर, 2008 को आयोजित किया गया। उक्त पुन: साक्षात्कार में प्रतिवादी योग्यता पैनल में एकमात्र योग्य उम्मीदवार था। अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की दिनांक 6.2.2009 और 24.3.2009 की रिपोर्ट के आधार पर, यह पाया गया कि मूल मार्कशीट की डुप्लिकेट स्वीकार न करने में डीओ समन्वयक अधिकारी और साक्षात्कार समिति (एल 2) द्वारा सारणी

में जांच अधिकारी की रिपोर्ट में विस्तृत विवरण के अनुसार एक उम्मीदवार की चूक की गई थी।

रिकॉर्ड आगे दिखाता है कि प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया

दिनांक 23.1.2010 सहित विभिन्न तिथियों पर दायर अनुस्मारक के साथ 24.8.2009 को कंपनी के अध्यक्ष के समक्ष एक अभ्यावेदन। सीनियर डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर ने दिनांक 3.06.2010 को संचार द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया कि "आवेदन और संलग्न दस्तावेजों को देखने पर यह पाया गया है कि रिलेशनशिप शपथ पत्र प्रारूप के अनुसार नहीं है। हमें खेद है कि इसके मद्देनजर आपका आवेदन अयोग्य पाया गया है। "

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, डीजीएम (आरसी) ने अपने नोट द्वारा दिनांक 13.8.2009 द्वारा प्रस्तुत राय को खारिज कर दिया

15. यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन कैसे किया गया जैसा कि जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक-आर 6) से स्पष्ट है। जांच अधिकारी ने जांच के सारांश में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया, जिसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"जांच का सारांश:

डीओ द्वारा उपलब्ध कराए गए/सौपे गए दस्तावेजों के आधार पर, साथ ही नीति दिशानिर्देश आरओ /6002 दिनांक 7.4.2005 एवं 4.4.2006 के आवेदन के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष है:

एल-1 समिति ने मूल्यांकन के लिए सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया है। हालाँकि, इस विचलन के बावजूद, एल-1 समिति ने मूल्यांकन के लिए सभी दस्तावेजों पर विचार किया है।

'बैंक सावधि जमा आदि के रूप में तरल नकदी और' अचल और चल संपत्ति'' के मामले में, जैसा कि मेरी रिपोर्ट में बताया गया है, वित्तीय क्षमता के लिए, एल-1 समिति, स्क्रीनिंग समिति ने दस्तावेजों को महत्व दिया है परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के पास भले ही 'कोई सहमति नहीं' का हलफनामा/पत्र उपलब्ध है। इसलिए, मेरे अंतिम मूल्यांकन में, नीति के अनुरूप 'बिना सहमति के दस्तावेजों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए अंतिम अंकों में बदलाव आया है. अतः उपरोक्त के अनुरूप अंतिम परिणाम इस प्रकार है।

साक्षात्कार समिति के अनुसार (योग्यता के अनुरूप):

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	कुल मार्क
1	श्री नीलेश एल. कुडालकर	56.50
2	डॉ. अशोक शंकरलाल ग्वालानी	55.33

3	श्री के. श्रीनाधा राव	54.33

स्क्रीनिंग कमेटी के अनुसार (योग्यता के अनुरूप):

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	कुल मार्क
1	श्री नीलेश एल. कुडालकर	59.0
2	श्री के. श्रीनाधा राव	57.0
3	डॉ. अशोक शंकरलाल ग्वालानी	52.0

जांच के अनुसार (योग्यता के अनुरूप):

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	कुल मार्क
1	डॉ. अशोक शंकरलाल ग्वालानी	56.78
2	श्री के. श्रीनाधा राव	53.63
3	श्री नीलेश एल. कुडालकर	48.52

उपरोक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि साक्षात्कार समिति, स्क्रीनिंग कमेटी और जांच अधिकारी ने तीन अलग-अलग समूहों में तीन उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जिसके कारण साक्षात्कार समिति, स्क्रीनिंग समिति और जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में उम्मीदवारों की स्थिति बदल गई।

16. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया और 24.12.2008 के बाद हुए आगे के घटनाक्रम पर चर्चा किए बिना, अपीलकर्ताओं को इसके पक्ष में आशय पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

हालाँकि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस रुख पर गौर किया कि एक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 'रिलेशनशिप हलफनामा' प्रारूप के अनुसार नहीं था, लेकिन यह चयन के मामले में इस तरह के अधूरे हलफनामे के प्रभाव पर चर्चा करने में विफल रहा।

17. आम तौर पर, यदि किसी पैनल के चयन या तैयारी के मामले में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो खराब पाए जाने वाले पैनल को फिर से व्यवस्थित करने के बजाय नए सिरे से चयन करना वांछनीय है। नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त प्राधिकारी, यह निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है कि क्या पैनल को हटा दिया जाना चाहिए और ऊपर बताए गए तथ्यों सी को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से चयन किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप किया चयन रद्द करना।

18. उपरोक्त कारणों से, हमारे पास उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तदनुसार, बॉम्बे उच्च

न्यायालय द्वारा पारित आदेश और निर्णय दिनांक 29.9.2010 को सक्षम प्राधिकारी को संबंधित पेट्रोल/डीजल खुदरा दुकानों को फिर से विज्ञापित करने और कानून के अनुसार नया चयन करने की स्वतंत्रता के साथ रद्द किया जाता है। उपरोक्त दिशानिर्देश एवम टिप्पणी के साथ अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

. अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती रेणुका सिंह हुड्डा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।